सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 08 चैत्र, 1944 (श०) / 29 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 11

(1)	शिक्षा विभाग	.. ..	09
(2)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	.. ..	01
(3)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	11

बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (संगीत) की परीक्षा

120. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में हजारों छात्र-छात्राएँ संगीत में अपने कैरियर निर्माण के लिये प्रतिबद्ध हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत दस वर्षों से संगीत विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस0टी0ई0टी0) नहीं होने के कारण बिहार के हजारों छात्र-छात्राएँ को अबतक निराशा ही हाथ लगी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (म्यूजिक) की परीक्षा अंतिम बार 2011 में लिया गया, लेकिन उसके पश्चात् पुन: 2021 तक इस टेस्ट को शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा नहीं लिया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (संगीत) की परीक्षा लेने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ

121. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुदानित विद्यालयों में राजकीयकृत विद्यालयों की तरह नि:शुल्क शिक्षण की व्यवस्था है, परंतु मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ अनुदानित विद्यालयों के विद्यार्थियों को नहीं मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ बिहार के अनुदानित विद्यालयों में देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वाल्मिकी टाइगर रिजर्व में बाघों की घटती संख्या

122. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के 26 जनवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''15 सालों में 21 जनवरी में 2 बाघों की मौत'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के एकमात्र ''वाल्मिकी टाइगर रिजर्व'' क्षेत्र में लगातार बाघों की मौत हो रही है और अब मात्र 47 बाघ बचे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोकसभा में 30 अप्रील, 1990 को तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक प्रश्न के जवाब में यह बताया था कि वाल्मिकी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 81 बाघ हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या घटने के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विश्वविद्यालयों के कर्मियों का वेतन भुगतान

123. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 2703/2017 में पारित आदेश के आलोक में चतुर्थ चरण में अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 17670/2017, सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 19205/2017, सी0 नम्बर 8213/2018 एवं अन्य दायर किये गये अपील में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि शिक्षक एवं कर्मियों को तीन माह के अंदर सेवा अन्तर्लिनीकरण के साथ वेतन भुगतान एवं अन्य सभी सुविधायें बहाल किया जाये किन्तु सचिव शिक्षा के पत्रांक 15/एम 1-04/2020-291, दिनांक 4 फरवरी, 2021 के द्वारा इन कर्मियों के कार्य करने पर रोक लगा दिया है, यदि हाँ, तो सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित विश्वविद्यालयों के कर्मियों के वेतन तथा अन्य सुविधायें बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

STET परीक्षा में EWS अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स एवं उम्र सीमा में छूट

124. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार एस0टी0ई0टी0, 2019 परीक्षा की विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 373/2019 में EWS (इकोनोमिकल वीकर सेक्शन) अभ्यर्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक का उल्लेख नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार एस0टी0ई0टी0, 2019 परीक्षा में EWS अभ्यर्थियों को पासिंग अंक में अन्य आरक्षित वर्ग के समान 5 प्रतिशत की छूट नहीं दी गयी है, जबकि एस0टी0ई0टी0, 2019 परीक्षा फॉर्म जब अधिसूचित किया गया था, तब उसमें EWS अभ्यर्थियों के लिये एक अलग कॉलम आरक्षित वर्गों की तरह रखा गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार EWS अभ्यर्थियों के लिये पासिंग मार्क्स एवं उम्र सीमा में अन्य आरक्षित वर्गों की तरह छूट देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किताबों से वंचित

125. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 नवम्बर, 2021 के अंक में छपी खबर शीर्षक "सरकारी स्कूलों में 45 फीसदी बच्चों के पास किताबें नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष के 2021-22 के सत्र में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 1 करोड़ बच्चे किताब से वंचित रह गये हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो उपर्युक्त 1 करोड़ बच्चों को किताबों से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य विषय की STET परीक्षा का आयोजन

126. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में वाणिज्य विषय के 1308 शिक्षकों के पद रिक्त है, परंतु वाणिज्य विषय की STET परीक्षा अबतक नहीं होने के कारण उक्त विषय के शिक्षकों की बहाली नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार वाणिज्य विषय की STET परीक्षा आयोजित कर +2 उच्च विद्यालयों में कबतक वाणिज्य विषय के शिक्षकों की बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान की स्वीकृति

127. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 9 जुलाई, 2021 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "195 वित्त रहित कॉलेजों का 6 सत्रों का अटका है अनुदान" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2007-08 से वित्त रहित कॉलेजों को सरकार द्वारा अनुदान देने की व्यवस्था लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग की लापरवाही के कारण राज्य के 195 वित्त रहित कॉलेजों को पिछले 6 सत्रों का अनुदान नहीं मिलने के कारण प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वित्त रहित कॉलेजों को वित्तीय अनुदान कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नन-जुडिशियल स्टाम्प की सुलभ उपलब्धता

128. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में नन-जुडिशियल स्टाम्प पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण अवैध तरीके से इसकी खरीद-बिक्री की जा रही है जिस कारण गरीब वर्ग के लोगों को जमीन के खरीद-बिक्री करने में आर्थिक क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में कबतक नन-जुडिशियल स्टाम्प की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना

129. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित खबर ''शिक्षा लोन मिलने में देरी से हजारों विद्यार्थी परेशान'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को 4 लाख तक के शिक्षा लोन का प्रावधान है और वर्ष 2021-22 में केवल 19 प्रतिशत छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा लोन मिलने में देरी होने का असर छात्रों के पढ़ाई पर पड़ता है एवं आर्थिक रुप से कमजोर छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना से मिलने वाले शिक्षा लोन प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ

130. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को चावल खरीदने हेतु राशि उनके खाते में दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अक्टूबर से दिसम्बर, 2021 तक की रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा नहीं भेजे जाने के कारण कक्षा 1 से 8 तक 1.19 करोड़ बच्चों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ खाते में नहीं जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 1.19 करोड़ बच्चों से संबंधित प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने का क्या औचित्य है ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--(1) अस्वीकारात्मक । प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को परिवर्तन मूल्य की निर्धारित राशि उनके खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2021 तक कक्षा 1 से 8 तक के 64,10,432 (चौसठ लाख दस हजार चार सौ बत्तीस) बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के परिवर्तन मूल्य की राशि खाते में दी जा चुकी है । शेष बच्चों को DBT के माध्यम राशि भेजने का कार्य किया जा रहा है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में उत्तर सन्निहित है । बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना में चावल खरीदने की राशि नहीं दी जाती है, उन्हें सूखा राशन (चावल) निर्धारित मात्रा में यथा वर्ग 1-5 में 100 ग्राम एवं वर्ग 6-8 में 150 ग्राम प्रति कार्य दिवस के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है । साथ ही परिवर्तन मूल्य (भोजन तैयार करने हेतु चावल को छोड़कर अन्य सामग्री यथा दाल, तेल, मसाला, नमक, सब्जी, ईंधन आदि) की राशि अलग से बच्चों को DBT के माध्यम दिया जाता है ।

पटना :
दिनांक 29 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 129(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550